



फूड सेफ्टी सेक्टर के प्रतिनिधियों ने खाद्य उत्पादों पर एफओपीएल चेतावनी पर दिया बल



चंडीगढ़, 12 अगस्त (पीपीडी न्यूज़) : हेल्थी फूड के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने की दिशा में कोलकाता में सम्पन्न हुई। सट्टेटिजिक प्लानिंग मीटिंग में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे सिटिजंस अवैरनेस ग्रुप (सीएजी) और स्थानीय उद्योग के प्रतिनिधियों का मत था कि भारत में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप फ्रंट आफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) का अनुसरण होना आवश्यक है। सीएजी के चैयरमैन सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि इस मीटिंग में देश भर से फूड सेक्टर के स्ट्रेकहोल्डर्स जुटे और इस दिशा में उठाये जाने वाले प्रयासों को कैसे प्रभावी बनाया जाये। उन सभी पहलुओं पर चिंतन मंथन किया। मीटिंग के दौरान फूड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ इस दिशा में प्रयासरत संगठन और एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों की भी व्यापक भागीदारी देखने को मिली। मीटिंग के आयोजक व कंप्यूटर वायस के सीईओ अशीम सन्याल ने बताया कि देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की खपत में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ने के साथ भारत, एफओपीएल को अपनाने को प्राथमिकता दे रहा। भारत ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बैक्टेरियल की सेल और खपत में उच्चतम दर दर्ज की है। यह प्रोडक्ट्स चीनी, नमक और एडिटिव्स में बहुत युक्त होते हैं। 2006-2019 के यूरोमीटर सेल्स डाटा के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पैकेज्ड जंक फूड और बैक्टेरियल सेक्टर मात्र 13 सालों में ही 42 गुणा बढ़ गया है जिसकी अनदेखी खपत चिंता का कारण है। इसके विपरीत सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का रोजगार सृजन के लिये एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखती है, वर्तमान में यह मार्केट 200 बिलियन डालर्स का है और भविष्य में यह 500 बिलियन डालर्स तक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस तेजी से पनप रहे सेक्टर के लिये एफओपीएल जैसे मापदंड जल्द लागू किये जाने चाहिये जिससे की उद्योग भी प्रभावित न हो और खपतकार लोगों के उनकी हेल्थ के प्रति भी सजग रखा जा सके। मीटिंग में भाग ले रहे एसोसिएट के उपाध्यक्ष मनीश अग्रवाल का मत था कि इंडियन फूड एमएसएमई के लिये एक बड़ा लक्ष्य पारंपरिक भोजन के हेल्थी वर्जन को अपनाना है जो वैश्विक निर्यात के अनुरूप है। इससे निर्यात के लिये एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। उनके अनुसार एफओपीएल के अनुरूप भारत, पारंपरिक स्नेक्स के लिये एक बड़ा बाजार विकसित कर सकता है। मीट के दौरान यह निष्कर्ष उभर कर आया कि वर्ष 2030 तक भारतीय उपभोक्ता प्रोसेस्ड और ब्रांडेड फूड उत्पादों में लगभग छह ट्रिलियन डालर्स खपत करेगा जिस पर एक चेतावनी रुपी अंकुश लगाने की आवश्यकता है और यह एफओपीएल के तत्काल लागू होने से ही संभव होगा।